

## स्वटिज़रलैंड द्वारा भारत का MFN दर्जा रद्द किया जाना

### प्रलिमिस के लिये:

मोस्ट फेवरेड नेशन क्लॉज़, [दोहरे कराधान बचाव समझौता](#), कर छूट, आरथकि सहयोग एवं विकास संगठन, [आयकर अधिनियम, 1961](#), [व्यापार और आरथकि भागीदारी समझौता](#), [युरोपीय मुक्त व्यापार संघ](#), [अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष](#), कर चोरी, [विश्व व्यापार संगठन](#), [मुक्त व्यापार समझौता](#)।

### मेन्स के लिये:

अंतरराष्ट्रीय कराधान में मोस्ट फेवरेड नेशन क्लॉज़ और दोहरे कराधान से बचाव समझौतों का महत्व।

**स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड**

### चर्चा में क्यों?

स्वटिज़रलैंड ने [दोहरे कराधान बचाव समझौते \(DTAA\)](#) के अंतर्राष्ट्रीय शामिल मोस्ट फेवरेड नेशन क्लॉज़ के तहत भारत का दर्जा रद्द करने का निर्णय लिया है।

- स्वटिज़रलैंड द्वारा 1 जनवरी 2025 से भारतीय संस्थाओं पर 10% की पूरव कर दर लागू की जाएगी।

### DTAA के MFN क्लॉज़ के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- भारत और स्वटिज़रलैंड के बीच DTAA: भारत और स्वटिज़रलैंड के बीच आय पर दोहरे कराधान से बचाव हेतु 2 नवंबर 1994 को DTC IN-CH (भारत-स्वटिज़रलैंड प्रत्यक्ष कर संधि) पर हस्ताक्षर किया गए थे। इसे वर्ष 2000 और वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था।
  - वर्ष 2010 के प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 11 में MFN क्लॉज़ शामिल है, जो DTAA के तहत स्वटिज़रलैंड द्वारा MFN का दर्जा वापस लेने का आधार है।

# FACT SHEET

**Nov 2, 1994:**  
Switzerland and India sign the original Double Taxation Convention (DTC IN-CH)

**Feb 16, 2000:**  
First amending protocol to the DTC IN-CH

**Aug 30, 2010:**  
Second amending protocol to the DTC IN-CH

**May 13, 2011:**  
India-Colombia Double Taxation Agreement signed; Lower dividend rates included

**July 26, 2011:**  
India-Lithuania Double Taxation Agreement signed; 5% withholding tax included

**July 5, 2018:**  
Lithuania joined OECD

**April 28, 2020:**  
Colombia joined OECD

**2021:**  
Delhi High Court upholds application of residual tax rates considering MFN clause

**October 19, 2023:** Supreme Court of India reverses Delhi High Court's ruling

- प्रोटोकॉल में **MFN क्लॉज़**: MFN क्लॉज़ से यह सुनिश्चित होता है कि भारत द्वारा आरथकि सहयोग एवं बिकास संगठन (OECD) के किसी तीसरे सदस्य देश को दी जाने वाली कम कर दरों की सुवधा वर्ष 2010 के प्रोटोकॉल के बाद हुई सहमति के अनुसार, स्वदिज़रलैंड पर भी स्वचालित रूप से लागू होगी।
  - MFN क्लॉज़ का उद्देश्य कराधान दरों में समानता बनाए रखना था।
- स्वदिज़रलैंड द्वारा **MFN** का दर्जा वापस लेने का कारण: वर्ष 2010 के प्रोटोकॉल के बाद भारत ने दो OECD सदस्यों अरथात् लथिआनिया (लाभांश पर 5% कर दर) और कोलंबिया (लाभांश पर 5% सामान्य कर दर) के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किये।
  - हालाँकि भारत ने यही रायिती कर दर स्वदिज़रलैंड को प्रदान नहीं की।
  - वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के बाद स्वदिज़रलैंड ने अपने MFN क्लॉज़ की व्याख्या मौरस्परकिता की कमी का हवाला देते हुए 1 जनवरी 2025 से पूर्व लागू 10% कर कटौती दर को वापस लेने का फैसला किया।
- भारत की प्रतक्रिया: भारत ने दावा किया कि MFN क्लॉज़ तब तक स्वतः लागू नहीं होता जब तक कि [आयकर अधिनियम, 1961](#) की धारा 90 के तहत आधिकारिक रूप से अधिसूचित न कर दिया जाए।
  - इसने आगे तर्क दिया कि यह क्लॉज़ केवल उन देशों पर लागू होता है जो 2010 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करते समय OECD के सदस्य थे।
  - अक्टूबर 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लिथिआनिया और कोलंबिया के वर्ष 2010 के बाद OECD में शामिल होने से MFN क्लॉज़ लागू नहीं होगा, इसलिये भारत को अपने लाभांश कर की दर को घटाकर 5% करने की आवश्यकता नहीं है।
    - लथिआनिया और कोलंबिया करमश: वर्ष 2018 और 2020 में OECD में शामिल हुए।
- DTAA के तहत भविष्य का कराधान: 1 जनवरी 2025 से कर की दर 10% होगी क्योंकि MFN क्लॉज़ अब लागू नहीं होगा। वर्ष 2018-2024 की अवधि की कर दर 5% है।
- नविश और व्यापार पर प्रभाव: स्वदिज़रलैंड ने स्पष्ट किया कि इस नियम से भारत और स्वदिज़रलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते या भारत में स्वसि नविश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
  - भारत और EFTA ने वर्ष 2024 में [व्यापार और आरथकि साझेदारी समझौते \(TEPA\)](#) पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके तहत भारत को 15 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी नविश (FDI) के रूप में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त होंगे।
    - [EFTA \(यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ\)](#) में आइसलैंड, स्वदिज़रलैंड, नॉर्वे और लकिटेंस्टीन शामिल हैं।

## भारत-स्वदिज़रलैंड नविश परदृश्य

- वाणज्य एवं उदयोग मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2000 से वर्ष 2023 के बीच भारत में स्वदिज़रलैंड का नविश प्रवाह 9.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे वह भारत में 12 वाँ सबसे बड़ा नविशक बन गया।
- [अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष \(IMF\)](#) के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में स्वसि नविश 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - IMF के अनुसार, स्वदिज़रलैंड भारतीय FDI शेररों का 8 वाँ सबसे बड़ा प्राप्तकरता है, जिसकी राशि 3.7 बिलियन अमरीकी डॉलर है।

- नेस्ले, ABB, नोवार्टसि, रोश, UBS और करेडिट सुइस सहति 330 से अधिक स्वेच्छियों ने मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, वत्तित, नर्सिमाण, सतत प्रौद्योगिकियों और ICT सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारत में नविश किया है।
- TCS, इफोससि, HCL टेक और वपिरो सहति लगभग 140 भारतीय कंपनियों ने स्वेच्छिज़रलैंड में लगभग 180 संस्थाओं में नविश किया है, जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी (32%) और लाइफ साइंस (21%) के क्षेत्र में हैं।

## स्वेच्छिज़रलैंड

- स्वेच्छिज़रलैंड, आधिकारिक तौर पर स्वेच्छि परसिंघ, मध्य यूरोप में एक छोटा प्रवतीय देश है, जो आलप्स परवतों, झीलों और घाटियों के लिये जाना जाता है।
- यह एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और लिकिटेंस्टीन से लगती है।
- यह सदियों से अपनी तटस्थिति के लिये प्रसिद्ध है।
  - परणामस्वरूप, स्वेच्छिज़रलैंड, वैश्वीष रूप से जनिवा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे करिड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समतिओं संयुक्त राष्ट्र
  - के लिये एक लोकप्रिय मुख्यालय स्थान है।
  - यह प्राप्तीय संघ और नाटो का सदस्य नहीं है।
- यह अपने गोपनीय बैंकिंग क्षेत्र (Secretive Banking Sector) के लिये भी जाना जाता है।



## भारत के साथ MFN दरजे के नलिंबन का क्या प्रभाव हो सकता है?

- बढ़ी हुई कर देयताएँ: स्वेच्छिज़रलैंड में परचिलन करने वाले भारतीय व्यवसायों को उच्च कर देयताओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि स्वेच्छिज़रलैंड से प्राप्त लाभांश पर रोक कर 5% से बढ़कर 10% हो जाएगा।
  - कर कटौती (प्रतिधिरोपण कर) कसी व्यक्ति (नविसी या अनविसी) पर लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी के रूप में भुगतान करते समय कर रोकने या कटौती करने का दायरिव है।
- सीमा पार कर विवाद: इस नलिंबन से संधिके प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में भारत और स्वेच्छिज़रलैंड के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है।
- कराधान में संरक्षणवाद: स्वेच्छिज़रलैंड का कदम भारत सहति देशों की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो घरेलू राजस्व की रक्षा के लिये संरक्षणवादी को अपना रहे हैं।
  - इस नियम को वैश्विक बदलाव के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ देश अपने कर आधार की सुरक्षा के लिये अधिक संरक्षणवादी नीतियाँ अपना रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय कर मानदंडों का विकास: यह नियम अन्य देशों को कर संधिविवाद में एक रूपता अपनाने के लिये प्रेरित कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पक्ष MFN जैसे आवश्यक खंडों पर एकमत हों।

## दोहरा कर बचाव समझौता (DTAA) क्या है?

- परचियः DTAA दो या दो से अधिक देशों के बीच एक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता है जिसका उद्देश्य समान आय पर दोहरे कराधान से बचना है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि आय घरेलू और विदेशी दोनों करों के अधीन नहीं होगी।
- DTAA के उद्देश्यः
  - दोहरे कराधान से बचावः एक ही आय पर दो बार कर का भुगतान करने से रोकता है।
  - वित्तीय अपवंचन की रोकथामः कर अपवंचन से निपटने के लिये सूचना साझा करने में सक्षम बनाता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहनः स्पष्ट कर नियमों और कम देयताओं के साथ सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देता है।
- DTAA की कार्यप्रणालीः
  - नविस और स्रोत-आधारित कराधानः DTAA नविस और स्रोत दोनों देशों के लिये कर अधिकारों को परभिष्ठि करता है।
  - क्रेडिट विधिः नविस देश को स्रोत देश में भुगतान कर्ये गये करों पर क्रेडिट प्राप्त होता है।
  - छूट पद्धतिः एक देश में आय पर कर लगाया जा सकता तथा दूसरे देश में छूट प्रदान की जा सकती है।
  - भारत का DATT: 94 से अधिक व्यापक DTAA और आठ प्रतिबिधिति DTAA के साथ, भारत सबसे बड़े DTAA नेटवर्कों में से एक है।

## MFN की स्थितिक्रिया है?

- परचियः वह व्यापारिक दर्जा जो दो देशों के बीच गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार की गारंटी देता है, MFN के रूप में जाना जाता है।
  - इसका अरथ अधिमान्य व्यवहार नहीं है, बल्कि यह गारंटी है कि प्राप्तकर्ता देश को अनुदान देने वाले देश के अन्य व्यापार साझेदारों की तुलना में नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- MFN और WTO: MFN विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का एक प्रमुख सदिधांत है।
  - विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत, यदि कोई देश किसी एक व्यापार साझेदार को विशेष दरजा देता है, तो यह दर्जसभी विश्व व्यापार संगठन सदस्यों को दिया जाना चाहिये।
- गैर-भेदभावपूर्ण व्यापारः समान व्यापार शर्तें प्रदान करके, MFN यह गारंटी देता है कि शर्टर एक दूसरे के साथ निषिक्ष व्यवहार करें। इन शर्तों में शामिल हैं:
  - न्यूनतम सम्भव व्यापार शुल्क और व्यापार बाधाएँ।
  - उच्च आयात कोटा
  - बाजार तक पहुँच में वृद्धि
  - वस्तु के प्रवाह के लिये बेहतर स्थितियाँ
- MFN के अपवादः
  - मुक्त व्यापार समझौते (FTA): FTA में शामिल देश गैर-सदस्यों को छोड़कर एक-दूसरे को विशेष रियायतें प्रदान करते हैं।
  - क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTA): सदस्य देश आपस में बेहतर शर्तों पर संवाद करते हैं, जिसमें अक्सर गैर-सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है।

## निषिकरणः

भारत के साथ अपने DTAA में MFN खंड को निलंबित करने का सवटिज़रलैंड का नियमित अंतर्राष्ट्रीय कराधान में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो कर संघर्षों में विकसित हो रहे वैश्वकि मानदंडों को उजागर करता है। यह परविरत्न सवटिज़रलैंड में परचियालन करने वाली भारतीय संस्थाओं के लिये कर देनदारियों को बढ़ा सकता है और सीमा पार नविश प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, जबकि स्पष्ट संधि वियाख्याओं की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

????????????????????????????: दोहरे कराधान और राजकोषीय अपवंचन को रोकने में दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA) की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????????????????????:

प्रश्न. अप्रवासी सततवां द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/है? (2018)

1. यह आय कर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है।
2. भारत में विज्ञापन सेवाएँ देने वाले अप्रवासी सततव अपने गृह देश में "दोहरे कराधान से बचाव समझौते" के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

Q. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक बड़ा हसिसा ब्रॉडबैंड और फ्रॉन्ट जैसी कई प्रमुख और प्रणिक्व अरथव्यवस्थाओं की तुलना में मौरीशस से आता है। क्यों? (2010)

- (a) FDI प्राप्त करने के संबंध में कुछ देशों के लिये भारत की प्राथमिकता है
- (b) भारत का मौरीशस के साथ दोहरा कराधान अपवंचन समझौता है
- (c) मौरीशस के अधिकांश नागरिकों की भारत के साथ जातीय पहचान है और इसलिये वे भारत में निवेश करने में सुरक्षित महसूस करते हैं
- (d) वैश्विक जलवायु परविरतन के आसनन खतरों के कारण मौरीशस को भारत में भारी निवेश करने के लिये प्रेरणा करते हैं।

उत्तर: (B)

?/?/?/?/?:

प्रश्न: केंद्रीय बजट, 2018-2019 में दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ कर (एल० सी० जी० टी०) तथा लाभांश वत्तिरण कर (डी० डी० टी०) के संबंध में प्रारंभ किये गए महत्वपूर्ण परविरतनों पर टपिक्स कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/switzerland-suspends-mfn-status-to-india>

